चयन समिति ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदन करने का प्रयास करेगी जिनमें सामाजिक मूल्य और स्वास्थ्य मनोरंजन हो विशेषरूप से उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी जो :

(i) अच्छे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दें ।

(ii) दर्शकों में विभिन्न धर्मों, विचारों, सांस्कृतियों इत्यादि के प्रति समान आदर की भावना उत्पन्न करें, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें और भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बढ़ावा दें ;

(iii) देश की समृद्धि सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट प्रतिबिम्बित करें।

(iv) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा दें और भारत के जनजीवन को प्रतिबिम्बित करें ।

(v) हमारे समाज में नारी के स्थान के प्रति स्वस्थ सम्मान को बढ़ावा दें और युवाओं की आकांक्षाओं और समस्याओं को उजागर करें; और

(vi) दर्शकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें ।

चयन समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों की उपयुक्तता की जांच करने के मामले में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए ।

निर्माता जिनके प्रस्ताव अस्थायी रूप से अनुमोदित किये गये हैं को अंतिम अनुमोदनार्थ-चयन समिति के सम्मुख रखने के लिये निश्चित समय के भीतर एक "पायलट" कार्यक्रम अपनी लागत और दायित्व पर निर्मित और प्रस्तुत करना होगा ।

कमीशण्ड धारावाहिक :

कमीशन्ड स्कीम के अधीन दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों पर केन्द्रों में उपयुक्त समिति द्वारा अनेक विषयगत मूल्य, स्क्रिप्ट का प्रतिपादन, शैक्षणिक, सूचनात्मक और निहित मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है । प्रस्तावों पर विचार करते समय रचनात्मक एवं तकनीकी दलों को उचित महत्व दिया जाता है । केन्द्र द्वारा उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों की लागत समिति के अंतिम अनुमोदन के लिए महानिदेशालय में भेजा जाता है ।

किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किये जाने के मानदण्ड

652. **डा. अरार अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए वर्तमान मानदण्ड कब बनाये गये थे और क्या बाद में समय-समय पर उन मानदण्डों में संशोधन या परिवर्तन किये गये थे, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन मानदण्डों को अभी भी उपयुक्त होना मानती है ; यदि नहीं, तो उन्हें कब तक बदल किये जाने की संभावना है ।

(ग) देश में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें एक भी बड़ा अथवा मध्यम दर्जे का उद्योग नहीं है और फिर भी वे औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं ; और

(घ) राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले की अभी तक उक्त श्रेणी में सम्मिलित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अपनाये जाने वाले दिशानिर्देशों के मानदंड राज्य सरकारों और संघ शासित

क्षेत्रों को दिसम्बर, 1969 में परिचालित किये गये। राज्य सरकारों की सिफारिशों पर योजना आयोग ने 246 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पाया। 1981 में जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना–1979–80 के अनुसार उन जिलों का पता लगाया था जिनमें कोई बड़े अथवा मझौले उद्योग नहीं थे। 93 जिलों को "उद्योग रहित जिला" के रूप में पाया गया। 1983 में भारत सरकार ने पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को तीन श्रेणियों "क", "ख" और "ग" के रूप में पुनः वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण अभी भी जारी है।

(घ) चूंकि सवाई माधोपुर औद्योगिक पिछड़ेपन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, अतः इसे पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया है।

Submission of documents by VHP and BMCA on disputed site at Ayodhya

653. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Vishwa Hindu Parishad and the Babri Masjid Action Committee have since submitted their documents and evidences to back up their claims on the disputed site at Ayodhya;

(b) whether Government have since examined the evidences submitted by VHP and BMAC; and

(c) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes Sir.

(b) The evidence are under examination.

(c) After the submission of the evidences by the concerned parties on 23.12.1990, their respective claims were exchanged between the parties for the purpose of filling rejoinders. The next meeting is scheduled for the 10th January, 1991.

Revision of pay scale of officers of public sector undertakings

654. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether it is a fact that delegation of Officer's Association of the Central Public Sector Undertakings met him recently for a comprehensive settlement of their pay scale revision?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): It is a fact that a delegation met the Prime Minister recently.

Inauguration of AIR Station at Alwar

655. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that inauguration of All India Radio Station at Alwar in Rajasthan has not taken place despite all necessary measures connected with broadcasting of programmes have been completed long back; and

(b) if so, by when this Station would be inaugurated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) There has been some delay in the formal inauguration of the Radio Station set up at Alwar in Rajasthan. However, in order to ensure that the facilities developed at considerable expenditure from public exchequer are not allowed to remain idle, Akashwani has been advised to operationalise the Radio Station at Alwar immediately without waiting for its formal inauguration.

Draft Service Rules of DSIDC

656. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1978 the Delhi State Industrial Development Corporation (DSIDC) adopted the Delhi